



Daily करेंट अफेयर्स

» 30 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विजन 2047 के तहत राजमार्ग दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत की पहली AI-आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू की।



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के दुर्घटना-प्रवण हिस्सों पर स्मार्ट निगरानी, भविष्यसूचक विश्लेषण और AI-संचालित प्रवर्तन उपकरणों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।

● केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में MoRTH द्वारा इस पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसे उत्तर प्रदेश के चुनिंदा उच्च-जोखिम वाले गलियारों पर लागू किया जाएगा, जिसमें वास्तविक समय पर यातायात निगरानी, उल्लंघनों का पता लगाने और AI तकनीकों का उपयोग करके त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पायलट परियोजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2025 में शुरू होगी।

● AI-आधारित प्रणाली में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे, गति पहचान रडार, लेन उल्लंघन सेंसर और AI-सक्षम ब्लैक स्पॉट मैपिंग शामिल होंगे। ये उपकरण यातायात अधिकारियों

को ओवरस्पीडिंग, गलत लेन में गाड़ी चलाने और सिग्नल जंपिंग जैसे उल्लंघनों की वास्तविक समय में निगरानी करने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद करेंगे।

● यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय (MHA) और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के समन्वय से क्रियान्वित की जाएगी। एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र राजमार्ग सेंसरों से अलर्ट प्राप्त करेगा और एम्बुलेंस एवं प्रवर्तन टीमों के साथ समन्वय करके आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ शुरू करेगा।

Key Points:-

(i) यह पहल नागपुर में iRASTE (प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान) परियोजना जैसे पहले के एआई सड़क सुरक्षा मॉडल से प्रेरित है, जिसे सितंबर 2021 में MoRTH, NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया), CSIR-CRRI (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान), और IIIT-हैदराबाद (अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-हैदराबाद) द्वारा लॉन्च किया गया था।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पायलट परियोजना, संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक के अनुरूप, 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50% तक कम करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करती है। यह परियोजना 12-18 महीनों तक चलेगी और उसके बाद प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर इसे देशव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।

(iii) उत्तर प्रदेश का पायलट प्रोजेक्ट "विज़न 2047" रणनीति के तहत भारत में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्रवर्तन को अपनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सफल होने पर, इसे उच्च दुर्घटना दर वाले अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा, जहाँ एआई

को राजमार्ग डिज़ाइन, रखरखाव और कानून प्रवर्तन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत की जलवायु लचीलापन को मजबूत करने के लिए 19वें स्थापना दिवस पर 14 वैज्ञानिक उपकरण लॉन्च किए।



28 जुलाई 2025 को, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा विकसित 14 नए वैज्ञानिक उपकरणों और डिजिटल सेवाओं का अनावरण किया। ये नवाचार भारत की जलवायु लचीलापन, आपदा तैयारी और जन-जन तक पहुँच को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- यह शुभारंभ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 19वें स्थापना दिवस समारोह के साथ हुआ, जिसका विषय था "19 साल - विज्ञान, संकल्प और सेवा", नई दिल्ली में आयोजित। मंत्री सिंह ने भारत के एक नागरिक-केंद्रित, विज्ञान-संचालित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन का वर्णन किया और मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुलभ वास्तविक समय के मौसम अलर्ट और समुद्री पूर्वानुमानों पर ज़ोर दिया।

- प्रस्तुत किए गए उपकरणों में भारत पूर्वानुमान प्रणाली - विस्तारित अवधि पूर्वानुमान (BharatFS-ERP), उच्च-रिज़ॉल्यूशन वर्षा डेटासेट,

चार शहरों के भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण मानचित्र, अद्यतन तरंग एटलस, फसल-मौसम कैलेंडर, महासागर जैव विविधता रिपोर्ट और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा "जीवन रक्षक प्रभाव" नामक एक वृत्तचित्र शामिल थे। ये उपकरण कृषि, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा के लिए सेवाओं को बेहतर बनाते हैं।

- डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछले दशक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के उल्लेखनीय विस्तार पर प्रकाश डाला: डॉपलर मौसम रडार 15 से बढ़कर 41 इकाई हो गए हैं, और भूकंपीय और मौसम निगरानी प्रणालियों को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया गया है - जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं को 2-3 मिनट के भीतर वास्तविक समय में भूकंप की चेतावनी मिल सके।

Key Points:-

(i) आज 7 लाख से ज़्यादा किसान मौसम पूर्वानुमान के आधार पर स्थान-विशिष्ट फसल सलाह के लिए मेघदूत मोबाइल ऐप पर निर्भर हैं। वहीं, तटीय मछुआरे सुरक्षित मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए SMS अलर्ट का लाभ उठा रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतिम छोर तक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों को व्यावहारिक पहुँच के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा है।

(ii) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्री प्रौद्योगिकी में भी अपनी अग्रणी भूमिका का प्रदर्शन किया, जहाँ लक्षद्वीप में छह महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) संयंत्र प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर पेयजल का उत्पादन कर रहे हैं। समुद्रयान परियोजना सहित डीप ओशन मिशन को भविष्य का आर्थिक प्रेरक बताया गया—जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र तल से 6 किमी नीचे गोता लगाने की परिकल्पना की गई है।

(iii) संस्थागत मजबूती पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) का बजट 2014 के ₹1,281 करोड़ से

बढ़कर 2024 में ₹3,658 करोड़ हो गया है, जिससे सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम प्रत्यूष और मिहिर जैसे उच्च-प्रदर्शन वाले बुनियादी ढाँचों को सहायता मिलेगी। इस बढ़ी हुई धनराशि ने मिशन मौसम, राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) जैसी प्रमुख पहलों को सक्षम बनाया और IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) सहित प्रमुख एजेंसियों के साथ साझेदारी को मजबूत किया।

INTERNATIONAL

1. संयुक्त राष्ट्र ने SOFI 2025 रिपोर्ट जारी की: वैश्विक भूख से 2024 में दुनिया की 8.2% आबादी प्रभावित होगी, अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।



28 जुलाई 2025 को, संयुक्त राष्ट्र ने "विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI) 2025" रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा किया गया कि लगभग 673 मिलियन लोग, या वैश्विक आबादी का 8.2%, 2024 में दीर्घकालिक भूख का अनुभव करेंगे। हालांकि 2023 में भूख 8.5% से थोड़ी कम हुई, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति असमान बनी हुई है।

• SOFI 2025 रिपोर्ट - जिसे FAO (खाद्य और कृषि संगठन), IFAD (कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष), यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष), WFP (विश्व

खाद्य कार्यक्रम) और WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है - से पता चलता है कि लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर भूख में कमी जारी रही, हालांकि इसका स्तर 2019 के पूर्व-महामारी आधार रेखाओं की तुलना में अधिक बना हुआ है।

• वैश्विक भूखमरी में कमी मुख्यतः दक्षिणी एशिया (विशेषकर भारत) और दक्षिण अमेरिका में हुई प्रगति के कारण हुई है, जहाँ भूखमरी दर क्रमशः 11% और 3.8% तक गिर गई है। ये सुधार पौष्टिक आहार तक बेहतर पहुँच, कृषि में प्रगति और प्रभावी सामाजिक सुरक्षा पहलों को दर्शाते हैं।

Key Points:-

(i) इसके विपरीत, अफ्रीका सबसे असुरक्षित क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ 2024 में 307 मिलियन लोग - या पांच में से एक - दीर्घकालिक रूप से कुपोषित होंगे। अफ्रीका में खाद्य-असुरक्षित लोगों का अनुपात 2030 तक वैश्विक कुल का लगभग 60% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो संघर्ष, जलवायु झटकों और धीमी कृषि उत्पादकता से प्रेरित है।

(ii) रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 2.3 बिलियन लोग - या जनसंख्या का 28% - 2024 में मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित थे। यह आंकड़ा अभी भी 2019 की तुलना में 355 मिलियन अधिक है और 2015 की तुलना में 683 मिलियन अधिक है जब संयुक्त राष्ट्र ने अपने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था।

(iii) जबकि कुपोषण में थोड़ी कमी आई, वैश्विक मोटापे की दर में वृद्धि हुई: वयस्क मोटापा 2022 तक 15.8% तक पहुंच गया, जो 2012 में 12.1% था, और बच्चों में बौनापन मामूली रूप से घटकर 2024 में 23.2% हो गया। रिपोर्ट में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को स्वस्थ आहार तक पहुंच में एक प्रमुख बाधा के रूप में रेखांकित किया गया है।

BANKING & FINANCE

1. ब्याज दर जोखिमों से निपटने के लिए LIC ने जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (FRA) पर हस्ताक्षर किए।



जुलाई 2025 में, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अमेरिका की दो प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थाओं—जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी (JPMorgan Chase & Co.) और बैंक ऑफ अमेरिका (BoA)—के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8,300 करोड़) के फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स (FRA) पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य गिरती ब्याज दरों के प्रभाव से अपने निवेश को सुरक्षित रखना और इक्विटी बाजार की अस्थिरता के बीच दीर्घकालिक रिटर्न को स्थिर बनाए रखना है।

- LIC द्वारा FRA लेन-देन में प्रवेश करने का निर्णय नवंबर 2024 की उस घोषणा के बाद आया, जिसमें उसने बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार में कदम रखने की योजना बताई थी। यह कदम एक रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन है, जो बीमा कंपनी के पोर्टफोलियो को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखने की दिशा में उठाया गया है।

- जुलाई 2025 तक, LIC ने पहले ही 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के FRA ट्रेड निष्पादित किए, जो भारत के कुल FRA बाजार (2.6 बिलियन डॉलर) का लगभग 38% हिस्सा है। यह दिखाता है कि इस

वित्तीय उपकरण खंड में LIC की कितनी मजबूत उपस्थिति है।

- फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (FRA) एक डेरिवेटिव अनुबंध होता है, जिसमें दो पक्ष भविष्य की किसी तिथि पर एक निश्चित ब्याज दर पर एक काल्पनिक राशि उधार देने या लेने पर सहमत होते हैं। इस अनुबंध में, LIC पहले से एक निश्चित ब्याज दर तय कर लेती है, जिससे भविष्य की ब्याज दरों में संभावित उतार-चढ़ाव का जोखिम समाप्त हो जाता है।

Key Points:-

(i) इन अनुबंधों में दूसरा पक्ष—जैसे जेपी मॉर्गन या बैंक ऑफ अमेरिका—ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन के जोखिम को अपने ऊपर लेता है और इसके बदले एक प्रीमियम प्राप्त करता है। अपने जोखिम को संतुलित करने के लिए, ये बैंक आम तौर पर उसी अवधि की परिपक्वता वाले दीर्घकालिक बॉन्ड खरीदते हैं, जिससे यह लेन-देन दोनों पक्षों के लिए लाभकारी बनता है।

(ii) LIC की यह FRA पहल उसकी निवेश रणनीति को अधिक लचीला बनाने और आर्थिक सुस्ती के समय ब्याज दरों में संभावित कटौती की स्थिति में भी स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. RBI ने मार्च 2025 में डिजिटल भुगतान सूचकांक में 10.7% की वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत बुनियादी ढांचे और प्रदर्शन वृद्धि को दर्शाता है।



जुलाई 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपना नवीनतम RBI-डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) डेटा जारी किया, जो मार्च 2025 में 493.22 तक 10.7% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, जो मार्च 2024 में 445.50 था। यह अर्ध-वार्षिक सूचकांक भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने और बुनियादी ढांचे की उन्नति की सीमा को दर्शाता है।

- RBI-डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) में वर्ष भर में 10.7% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो मार्च 2024 में 445.50 से बढ़कर मार्च 2025 में 493.22 हो गई, और सितंबर 2024 में 465.33 से भी सुधार दिखा। यह निरंतर वृद्धि देश भर में बढ़ती डिजिटल भुगतान पहुंच और लेनदेन की मात्रा को उजागर करती है।

- सूचकांक में यह उछाल मुख्य रूप से दो प्रमुख घटकों - भुगतान अवसंरचना-आपूर्ति पक्ष और भुगतान प्रदर्शन - के कारण हुआ। भुगतान स्वीकृति उपकरणों की बेहतर उपलब्धता, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और कुशल भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- RBI-DPI को पहली बार 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतानों के अपनाने और उनकी पहुंच पर नज़र रखने के एक समग्र उपाय के रूप में लॉन्च किया गया था। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पहलों और वित्तीय प्रौद्योगिकी विस्तार की प्रगति का आकलन करने के

लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

Key Points:-

(i) डिजिटल भुगतान सूचकांक वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है - मार्च और सितंबर के महीनों को कवर करते हुए - और मार्च 2018 को इसकी आधार अवधि के रूप में उपयोग करता है, जिसे 100 के मूल्य पर अनुक्रमित किया जाता है। यह आधार रेखा समय के साथ विकास प्रक्षेपवक्र और प्रणालीगत सुधारों को समझने में मदद करती है।

(ii) RBI-DPI में पाँच सावधानीपूर्वक संरचित घटक शामिल हैं: भुगतान सक्षमकर्ता (25%), भुगतान अवसंरचना-माँग-पक्ष (10%), भुगतान अवसंरचना-आपूर्ति-पक्ष (15%), भुगतान प्रदर्शन (45%), और उपभोक्ता-केंद्रितता (5%)। ये मानदंड डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं।

(iii) भारत में डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12,000 लाख करोड़ रुपये (120 ट्रिलियन रुपये) से अधिक मूल्य के 65,000 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म में बढ़ते विश्वास और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने वाली निरंतर सरकारी पहलों को दर्शाता है।

3. CCI ने RNAIPL में रेनॉल्ट समूह की हिस्सेदारी अधिग्रहण और अनंतम हाईवेज ट्रस्ट द्वारा सड़क परिसंपत्ति सौदों को मंजूरी दी।



28 जुलाई 2025 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तहत कार्यरत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दो प्रमुख अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी: रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (RNAIPL) में रेनॉल्ट समूह की शेष हिस्सेदारी का अधिग्रहण, और अनंतम हाईवे ट्रस्ट द्वारा सड़क परिसंपत्ति का अधिग्रहण, जो ऑटोमोटिव और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समेकन को दर्शाता है।

- पहले CCI-अनुमोदित सौदे में रेनॉल्ट ग्रुप बी.वी. और उसके नामित रेनॉल्ट एस.ए.एस. ने निसान मोटर कंपनी लिमिटेड और निसान ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. सहित उसके सहयोगियों से रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (.RNAIPL) में शेष 51% हिस्सेदारी हासिल की, जिससे भारतीय उद्यम में रेनॉल्ट का पूर्ण स्वामित्व मजबूत हो गया।

- इस ऑटोमोटिव सौदे के तहत प्रस्तावित संयोजन में निसान, जापान और उसकी संस्थाओं से इक्विटी शेयरों के साथ-साथ शून्य-कूपन गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों (पूर्णतः चुकता) का अधिग्रहण शामिल है। इस अधिग्रहण से रेनॉल्ट को भारतीय बाजार में विनिर्माण और संचालन पर नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिलेगी।

- दूसरे सौदे में, CCI ने अनंतम हाईवे ट्रस्ट द्वारा सड़क अवसंरचना परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को

मंजूरी दी, जो एक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvIT) है, जिसे मुंबई स्थित अल्फा अल्टरनेटिक्स फंड एडवाइजर्स LLP और प्रायोजक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (DBL) और DBL इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन प्राप्त है।

Key Points:-

(i) अनंतम सौदे में आठ लक्षित विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) में पूर्ण 100% शेयरधारिता शामिल है, जिसमें डोड्डाबल्लापुर होसकोटे राजमार्ग, रेपल्लेवाड़ा राजमार्ग, छिंदवाड़ा राजमार्ग जैसी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियां और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले अन्य राजमार्ग शामिल हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, इस सौदे में सड़क परिसंपत्ति इकाई PHL इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी शामिल है, जिससे अनंतम के राजमार्ग रियायतों के पोर्टफोलियो का और विस्तार होगा और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा निवेश व्यवहार्यता में सुधार होगा।

(iii) CCI द्वारा ये अनुमोदन भारत सरकार के व्यापार में आसानी और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के अनुरूप हैं, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश और रणनीतिक परिसंपत्ति समेकन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

ECONOMY & BUSINESS

1. IMF ने बेहतर वैश्विक परिदृश्य के बीच वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया।



विश्व आर्थिक परिदृश्य के अपने जुलाई 2025 के अद्यतन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27, दोनों के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.4% कर दिया है—जो अप्रैल के पूर्वानुमान में क्रमशः 6.2% और 6.3% था। यह वृद्धि एक अधिक अनुकूल बाहरी वातावरण और मज़बूत घरेलू सुधारों की गति को दर्शाती है।

- IMF ने वित्त वर्ष 2026 में भारत के विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों और वित्त वर्ष 2027 में 10 आधार अंकों तक बढ़ा दिया है, और इस वृद्धि का श्रेय वैश्विक टैरिफ में ढील, कमजोर अमेरिकी डॉलर सहित बेहतर वित्तीय स्थिति और उपभोग और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने वाले निरंतर सुधार प्रयासों जैसे कारकों को दिया है।

- वैश्विक स्तर पर, IMF ने अब 2025 में 3.0% और 2026 में 3.1% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, साथ ही उभरते बाजारों की वृद्धि को 2025 के लिए 4.1% और 2026 के लिए 4.0% तक संशोधित किया है। चीन का पूर्वानुमान 4.8% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

- संशोधित पूर्वानुमान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को और मज़बूत करता है। वैश्विक मंदी के बावजूद, आईएमएफ ने चीन और अमेरिका जैसे

समकक्ष देशों की तुलना में भारत की विकास दर को आगे बढ़ाने की पुष्टि की है, जिससे भारत की आर्थिक बुनियाद में निवेशकों का विश्वास मज़बूत हुआ है।

Key Points:-

(i) IMF ने चेतावनी दी है कि टैरिफ़ तनाव या राजकोषीय घाटे में वृद्धि से विकास की गति पटरी से उतर सकती है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है और वित्तीय स्थितियाँ और भी कठिन हो सकती हैं। इसने विकास को बनाए रखने के लिए शिक्षा, श्रम बाज़ार, भूमि नीतियों और नियामक सुगमता में निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

(ii) संशोधित पूर्वानुमान के आधार पर, IMF ने भारत को कृषि श्रमिकों के कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार सृजन बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में निवेश को बनाए रखने और डिजिटल तथा विनिर्माण सुधारों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है - ये सभी भारत के दीर्घकालिक विकास और समावेशन एजेंडे को बल प्रदान करते हैं।

2. भारत की कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था 2032 तक 12 मिलियन नौकरियाँ पैदा करेगी, जिससे द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।



वैश्विक प्रतिभा समाधान फर्म NLB सर्विसेज़ की जुलाई 2025 में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तेज़ी से बढ़ती संगीत अर्थव्यवस्था 2030-2032 तक लगभग 12 मिलियन (1.2 करोड़) अस्थायी नौकरियाँ पैदा करेगी। इस उछाल का कारण सालाना 100 से ज़्यादा बड़े प्रारूप वाले संगीत कार्यक्रम हैं, जो महानगरों से परे आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं।

● जबकि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में बड़े आयोजन जारी हैं, वहीं कॉन्सर्ट गतिविधियाँ गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, पुणे, जयपुर, शिलांग, इंदौर और चंडीगढ़ जैसे टियर II और III शहरों में फैल रही हैं, जिससे पूरे देश में नए अवसर और सांस्कृतिक जीवंतता पैदा हो रही है।

● प्रत्येक बड़े कॉन्सर्ट में आयोजन स्थल संचालन, भीड़ प्रबंधन, खाद्य एवं पेय सेवाएँ, मंच सज्जा, कलाकार प्रबंधन, रसद, डिजिटल मीडिया और सामग्री निर्माण जैसे कार्यों में 15,000 से 20,000 अस्थायी भूमिकाएँ उत्पन्न होती हैं। इनमें से लगभग 10-15% भूमिकाएँ प्रोडक्शन प्रबंधन, ऑडियो इंजीनियरिंग और डिजिटल रणनीति जैसे क्षेत्रों में पूर्णकालिक करियर में परिवर्तित हो रही हैं।

● कॉन्सर्ट ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मापने योग्य तरीकों से बढ़ावा दिया है—अहमदाबाद में कोल्डप्ले के 2024 के दौरे ने अकेले शहर की अर्थव्यवस्था में लगभग ₹641 करोड़ का निवेश किया, जिसमें ₹72 करोड़ का GST राजस्व, उड़ानों की माँग में 300-350% की वृद्धि, ट्रेन बुकिंग में उछाल और होटल के किराए में रिकॉर्ड वृद्धि शामिल है। इसका व्यापक प्रभाव यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य, खुदरा और MSMEs को लाभ पहुँचाता है।

Key Points:-

(i) तेज़ी से बढ़ती माँग के बावजूद, कुशल पेशेवरों की कमी—खासकर लाइव प्रोडक्शन, लाइटिंग डिज़ाइन, ऑडियो इंजीनियरिंग और डिजिटल इवेंट टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में—एक चुनौती बनी हुई है। उद्योग के

हितधारक, विशेष रूप से महानगरों के बाहर उभरते इवेंट हब में, कौशल उन्नयन और संरचित प्रशिक्षण में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं।

(ii) प्रति वर्ष 100 से ज़्यादा बड़े संगीत समारोहों की उम्मीद के साथ, भारत की संगीत अर्थव्यवस्था का आर्थिक मूल्य जल्द ही ₹15,000 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। यह उद्योग अब सकल घरेलू उत्पाद और युवा रोज़गार में एक औपचारिक योगदानकर्ता के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे एक स्थायी और समावेशी मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिल रही है।

3. रिलायंस जियो ने जियोपीसी लॉन्च किया - भारत का पहला AI-रेडी क्लाउड डेस्कटॉप जो किसी भी टीवी को कंप्यूटर में बदल देगा।



जुलाई 2025 में, दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने JioPC पेश किया, जो एक AI-रेडी, क्लाउड-आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफ़ॉर्म है जो जियो सेट-टॉप बॉक्स (STB) से जुड़े किसी भी टेलीविज़न को पूरी तरह कार्यात्मक डेस्कटॉप अनुभव में बदल देता है। जियोफाइबर और जियो एयरफाइबर दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध, यह प्लेटफ़ॉर्म पूरे भारत में किफायती कंप्यूटिंग पहुँच प्रदान करता है।

- जियोपीसी सब्सक्रिप्शन-फर्स्ट, पे-एज़-यू-गो मॉडल पर काम करता है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹400-₹599 प्रति माह (जीएसटी सहित) है, और इसमें किसी भी प्रकार की अग्रिम लागत या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। नए उपयोगकर्ताओं को एक महीने का निःशुल्क परीक्षण मिलता है, जिससे पारंपरिक पीसी के बिना भी उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग उन घरों तक पहुँच पाती है।

- इस सेवा के लिए एक जियो सेट-टॉप बॉक्स (ब्रॉडबैंड प्लान के साथ उपलब्ध या ₹5,499 में खरीदा जा सकता है), कोई भी HDMI-संगत टीवी, और एक कीबोर्ड व माउस ज़रूरी है। एक बार सेटअप हो जाने पर, उपयोगकर्ता की टीवी स्क्रीन जियो के रिमोट सर्वर से संचालित एक इंटरैक्टिव क्लाउड डेस्कटॉप बन जाती है।

- JioPC को ई-लर्निंग, रिमोट वर्किंग, कैजुअल ब्राउज़िंग और बुनियादी उद्यमिता को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को घर बैठे अपने टीवी का उपयोग करके ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने, दस्तावेज़ों को संपादित करने, उत्पादकता टूल लागू करने और डिजिटल सामग्री बनाने में सक्षम बनाता है। भविष्य के अपडेट में प्रिंटर और वेबकैम जैसे बाह्य उपकरणों के लिए सपोर्ट शामिल हो सकता है।

Key Points:-

(i) जियोपीसी पूरी तरह से जियो के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट किए गए उबंटू (लिनक्स) ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। यह वर्चुअल डेस्कटॉप तेज़ बूट-अप, 512 जीबी क्लाउड स्टोरेज, मैलवेयर और वायरस से नेटवर्क-स्तरीय सुरक्षा और बिल्ट-इन अपग्रेडेबिलिटी प्रदान करता है—जो हार्डवेयर अपडेट के बिना निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

(ii) जियोपीसी में लिबरऑफिस पहले से इंस्टॉल आता

है, यह ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस प्रदान करता है और इसमें एआई-रेडी उत्पादकता उपकरण शामिल हैं। सब्सक्राइबर्स को एडोब एक्सप्रेस का निःशुल्क एक्सेस भी मिलता है, जिससे कंटेंट निर्माण, ग्राफिक एडिटिंग और सीखने की सुविधा मिलती है—जिससे यह प्लेटफॉर्म छात्रों, पेशेवरों और रचनाकारों के लिए उपयुक्त है।

(iii) चूँकि केवल 15% भारतीय परिवारों के पास पीसी है, जबकि 70% से ज़्यादा परिवारों के पास टीवी हैं, इसलिए जियोपीसी करोड़ों लोगों तक पहुँचने की क्षमता रखता है, खासकर वंचित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढाँचे के माध्यम से व्यक्तिगत कंप्यूटिंग को लोकतांत्रिक बनाकर भारत के डिजिटल विभाजन को पाटना है।

MOUs and Agreement

1. DPIIT और एथर एनर्जी ने 'बिल्ड इन भारत' पहल के तहत ईवी विनिर्माण और स्वच्छ गतिशीलता में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



जुलाई 2025 में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के अंतर्गत कार्यरत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी एथर एनर्जी लिमिटेड के साथ

एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत में स्वच्छ गतिशीलता, उन्नत विनिर्माण और गहन तकनीकी स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार की 'बिल्ड इन भारत' पहल का एक प्रमुख घटक है।

- DPIIT के संयुक्त सचिव संजीव सिंह और एथर एनर्जी लिमिटेड के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तरुण मेहता की उपस्थिति में औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। यह समझौता भारत की स्वच्छ-तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के बुनियादी ढाँचे एवं विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक सार्वजनिक-निजी तालमेल का प्रतीक है।

- यह साझेदारी स्टार्टअप पॉलिसी फोरम (SPF) द्वारा संचालित 'बिल्ड इन भारत' पहल का हिस्सा है, जो 50 से ज़्यादा नवाचार-आधारित भारतीय स्टार्टअप्स का एक सामूहिक मंच है। इस पहल का उद्देश्य सरकार और उद्योग जगत के केंद्रित सहयोग से आत्मनिर्भर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और गहन तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना है।

- MoU की शर्तों के तहत, DPIIT और एथर एनर्जी डीप-टेक स्टार्टअप्स, खासकर EV वैल्यू चेन से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए 'रणनीतिक मार्गदर्शन' प्रदान करने हेतु संयुक्त रूप से काम करेंगे। MoU में मोबिलिटी टेक्नोलॉजी में नवाचार को बढ़ावा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हब स्थापित करने में सहायता भी शामिल है।

Key Points:-

(i) इस साझेदारी के मुख्य लाभों में से एक "भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज" जैसे सह-ब्रांडेड राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का शुभारंभ शामिल है। ये पहल प्रारंभिक चरण के नवाचार को बढ़ावा देंगी, प्रतिभाओं को बढ़ावा देंगी और भारत के इलेक्ट्रिक और टिकाऊ परिवहन मिशन से जुड़े उभरते स्टार्टअप्स के साथ

जुड़ेंगी।

(ii) यह सहयोग EV निर्माण क्षेत्र में कौशल संवर्धन और प्रतिभा विकास पर भी ज़ोर देता है। इसमें युवाओं और स्टार्टअप संस्थापकों में उद्यमशीलता और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग-केंद्रित कार्यशालाओं, बूट कैंपों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल होगा।

(iii) यह समझौता ज्ञापन स्टार्टअप महाकुंभ जैसे प्रमुख राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमों में भागीदारी को और मज़बूत करेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ गतिशीलता स्टार्टअप्स के लिए दृश्यता और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों, औद्योगिक विकास रणनीतियों और सतत प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ निकटता से जुड़ी हुई है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. शैलेश जेजुरिकर को प्रॉक्टर एंड गैम्बल (P&G) का अध्यक्ष और वैश्विक CEO नियुक्त किया गया।



प्रॉक्टर एंड गैम्बल (Procter & Gamble – P&G) ने जुलाई 2025 के अंत में घोषणा की कि इसके मुख्य परिचालन अधिकारी (Chief Operating Officer) शैलेश जेजुरिकर, 1 जनवरी 2026 से कंपनी के अध्यक्ष (President) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer – CEO) के रूप में जॉन

मोलर का स्थान लेंगे। जॉन मोलर कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) की भूमिका में स्थानांतरित होंगे। शैलेश जेजुरिकर, P&G के 187 वर्षों के इतिहास में पहले भारतीय मूल के नेता बनेंगे।

● जेजुरिकर 1989 में भारत में सहायक ब्रांड प्रबंधक के रूप में P&G में शामिल हुए और अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में वैश्विक भूमिकाओं में लगातार आगे बढ़े। 2021 में मुख्य परिचालन अधिकारी बनने से पहले, उन्होंने टाइड, एरियल, डाउनी और स्विफ्टर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों सहित वैश्विक फैब्रिक और होम केयर विभाग का नेतृत्व किया।

● जेजुरिकर की पदोन्नति एक ऐतिहासिक क्षण है: वह पी एंड जी के प्रमुख बनने वाले पहले भारत में जन्मे व्यक्ति होंगे। वह सत्य नडेला, सुंदर पिचाई और शांतनु नारायण जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के प्रतिष्ठित अधिकारियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

● पी एंड जी ने ज़ोर देकर कहा कि यह कदम बोर्ड द्वारा एक सुनियोजित और व्यवस्थित उत्तराधिकार है। 1 जनवरी 2026 को, जेजुरिकर सीईओ का पदभार संभालेंगे, जबकि जॉन मोलर कॉर्पोरेट प्रशासन और मार्गदर्शन की देखरेख के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में आएंगे।

Key Points:-

(i) जेजुरिकर अमेरिकी बिक्री में मंदी, बढ़ते टैरिफ, आर्थिक अनिश्चितता और हाल ही में घोषित पुनर्गठन योजना, जिसमें नौकरियों में कटौती और विनिवेश शामिल हैं, जैसे दबावों के बीच नेतृत्व संभाल रहे हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि वे विकास और नवाचार को आगे बढ़ाते हुए परिचालन स्थिरता बनाए रखेंगे।

(ii) पी एंड जी बोर्ड के प्रमुख निदेशक जो जिमेनेज़ ने जेजुरिकर की गहरी संस्थागत अंतर्दृष्टि और विभिन्न विभागों में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक "उत्कृष्ट नेता" बताया जो वैश्विक चुनौतियों के

दौरान पी एंड जी का मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं। बोर्ड ने उन्हें अक्टूबर 2025 की शेयरधारक बैठक में निदेशक पद के लिए भी नामित किया।

AWARDS

1. भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने डेज़ी रॉकवेल द्वारा अनुवादित 'वन्स एलिफेंट्स लिब्ड हियर' के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जीता।



जुलाई 2025 में, भारतीय हिंदी उपन्यासकार और लघु कथाकार गीतांजलि श्री को उनके लघु कहानी संग्रह 'वन्स एलिफेंट्स लिब्ड हियर' के लिए इंग्लिश पेन (UK) द्वारा प्रतिष्ठित पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 के 14 प्राप्तकर्ताओं में से एक नामित किया गया था, जिसका अंग्रेजी में प्रसिद्ध अमेरिकी अनुवादक डेज़ी रॉकवेल ने अनुवाद किया था।

● गीतांजलि श्री की पुस्तक "वन्स एलिफेंट्स लिब्ड हियर" को अपनी सशक्त कथा के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है, जो स्मृति, जड़ से उखड़ने और सांस्कृतिक व पारिस्थितिक विरासत के क्षरण जैसे गहन विषयों की पड़ताल करती है। यह पुरस्कार इंग्लिश पेन द्वारा दिया जाता है, जो ब्रिटेन स्थित एक साहित्यिक और मानवाधिकार संगठन है और वैश्विक साहित्यिक अनुवाद को बढ़ावा देता है।

● "वन्स एलिफेंट्स लिब्ड हियर" का अंग्रेजी अनुवाद डेज़ी रॉकवेल ने किया है, जो एक प्रसिद्ध

अमेरिकी अनुवादक हैं और हिंदी और उर्दू की प्रमुख कृतियों के अनुवाद के लिए जानी जाती हैं। इस पुस्तक का अनुवाद एक सफल सहयोग को दर्शाता है जो भाषाई और सांस्कृतिक विभाजनों को पाटता है और वैश्विक साहित्यिक विमर्श में भारत की स्थिति को और मज़बूत करता है।

● गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। उन्होंने 1987 में लघु कथा "बेल पत्र" से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की, जिसके बाद 1991 में उनका पहला संग्रह "अनुगूंज" प्रकाशित हुआ। उनकी प्रमुख रचनाओं में "माई", "हमारा शहर उस बरस", "खाली जगह", "रेत समाधि" और "रेत का मकबरा" शामिल हैं।

Key Points:-

(i) 2022 में, गीतांजलि श्री ने इतिहास रच दिया जब रेत समाधि (डेज़ी रॉकवेल द्वारा अंग्रेज़ी में अनुवादित टॉम्ब ऑफ़ सैंड) ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, जिससे वह यह वैश्विक सम्मान पाने वाली पहली हिंदी लेखिका बन गईं। उनका नवीनतम पेन पुरस्कार अनुवाद में दक्षिण एशियाई साहित्य की अग्रणी के रूप में उनकी पहचान को और मज़बूत करता है।

(ii) पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड, भाषाई विविधता और वंचितों की आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साहित्य के अंग्रेज़ी में अनुवाद को समर्थन देने हेतु इंग्लिश पेन की पहल का एक हिस्सा है। 2025 में, 13 भाषाओं और 11 वैश्विक क्षेत्रों से 14 कृतियों का चयन किया गया, जिनमें मोहम्मद अल-असद और कॉन्सेइसाओ एवरिस्टो जैसे लेखक शामिल हैं।

(iii) 2025 संस्करण में इस पुरस्कार ने दक्षिण एशियाई साहित्य पर विशेष ध्यान दिया, जिसे 'PEN Translates x SALT (South Asian Literature in Translation)' नामक सहयोग के तहत शिकागो विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया संस्थान के साथ मिलकर प्रस्तुत किया गया। गीतांजलि की पुस्तक के

साथ-साथ, सारा शगुप्ता की पुस्तक Eyes, Eyes, Eyes (जिसे उर्दू से जावेरिया हसनैन ने अनुवाद किया है) को भी मान्यता दी गई।

App and Web Portal

1. दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ावा देने और देश भर में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए 21 भारतीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।



17 जनवरी 2025 को, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली में संचार साथी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित यह ऐप 21 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और 90 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार धोखाधड़ी और अनधिकृत उपयोग से निपटने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

● संचार साथी, मई 2023 में शुरू किए गए पहले संचार साथी पोर्टल पर आधारित है, जो नागरिकों को दूरसंचार धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) का उपयोग करके खोए या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को ब्लॉक करने और अपने नाम से जुड़े मोबाइल कनेक्शन प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। ऐप

संस्करण इन सुविधाओं को आसान पहुँच के साथ एक मोबाइल इंटरफ़ेस में सुव्यवस्थित करता है।

- चक्षु नामक एक विशिष्ट सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने फ़ोन लॉग से संदिग्ध धोखाधड़ी संचार (SFC)—कॉल, SMS या व्हाट्सएप संदेश—की सीधे रिपोर्ट करने की सुविधा देती है। अन्य मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI) के माध्यम से हैंडसेट की प्रामाणिकता सत्यापित करने, स्थानीय मोबाइल नंबरों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय नकली कॉल की रिपोर्ट करने और अनधिकृत कनेक्शन ब्लॉक करने की सुविधा देते हैं।

- ऐप का बहुभाषी इंटरफ़ेस हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी और अन्य सहित 21 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है—जिससे यह पूरे देश में अद्वितीय रूप से सुलभ हो जाता है। इस लॉन्च का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी भारत में 90 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करना है।

Key Points:-

(i) लॉन्च समारोह में, मंत्री सिंधिया ने दूरसंचार सुरक्षा और उपयोगकर्ता विश्वास को बढ़ाने में ऐप की भूमिका पर जोर दिया, और कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन का विस्तार करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित 4 जी मोबाइल साइटों पर राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) 2.0 और इंटर-सर्किल रोमिंग जैसी पूरक पहलों का उल्लेख किया।

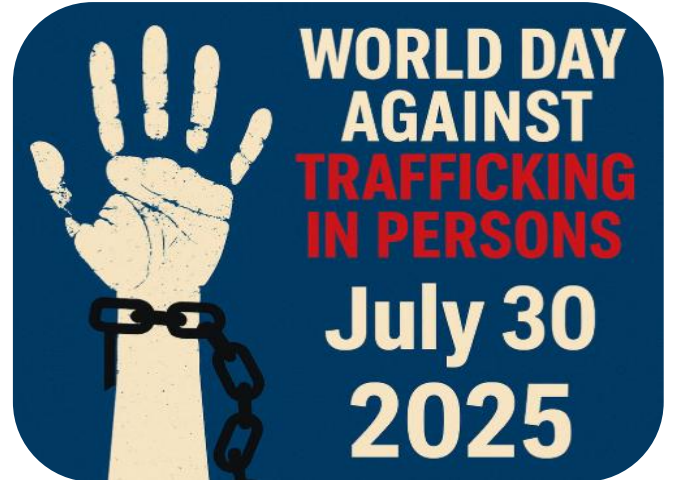
(ii) पोर्टल की शुरुआत से अब तक, 9 करोड़ से ज्यादा विज़िट के कारण 2.75 करोड़ धोखाधड़ी वाले कनेक्शन काटे गए हैं, 25 लाख चोरी हुए फ़ोन बरामद किए गए हैं, साइबर अपराध से जुड़े 12.38 लाख व्हाट्सएप अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और 11.6 लाख म्यूल बैंक अकाउंट निलंबित किए गए हैं।

संचार साथी मोबाइल ऐप से उपयोगकर्ता जुड़ाव में वृद्धि के ज़रिए इन परिणामों में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

(iii) एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफ़ार्मों के लिए उपलब्ध, ऐप को जून 2025 तक प्ले स्टोर पर 40 लाख से अधिक और ऐप्पल ऐप स्टोर पर 3.6 लाख से अधिक डाउनलोड मिले हैं। गोपनीयता सुरक्षा उपायों में रिपोर्टिंग के दौरान केवल कॉल/एसएमएस लॉग तक सीमित पहुंच शामिल है, और डेटा केवल जांच उद्देश्यों के लिए दूरसंचार विभाग के साथ साझा किया जाता है।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस 2025, 30 जुलाई को मनाया गया।



हर साल 30 जुलाई को, दुनिया मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाती है, जिसकी स्थापना 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 2025 का विषय - "मानव तस्करी संगठित अपराध है - शोषण को समाप्त करें" - वैश्विक तस्करी नेटवर्क को खत्म करने और न्याय-प्रणाली सुधारों और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोणों के माध्यम से बचे लोगों की रक्षा करने पर जोर देता है।

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने आधिकारिक संदेश में मानव तस्करी को दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते संगठित अपराधों में से एक

बताया। उन्होंने दंड से मुक्ति को समाप्त करने, अवैध मुनाफ़े पर लगाम लगाने और कमज़ोर लोगों की सुरक्षा के लिए आपराधिक न्याय प्रणालियों को मज़बूत करने हेतु वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया।

- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के अनुसार, 2020 से 2023 तक दुनिया भर में 2,00,000 से ज़्यादा पीड़ितों का पता चला— सिर्फ़ दिखाई देने वाले लोग। दुनिया भर में, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग गुलामी में हैं, जिनमें 70% से ज़्यादा महिलाएँ और लड़कियाँ हैं और लगभग 38% मामले बच्चों के हैं।

- 2025 के अभियान का विषय इस बात पर ज़ोर देता है कि तस्करी एक सुनियोजित आपराधिक उद्यम है। इसमें अभियोजन से लेकर पीड़ितों की सहायता तक, कानूनी और प्रवर्तन ढाँचों में सुधार की माँग की गई है। इस विषय का मुख्य उद्देश्य सिंडिकेट को ध्वस्त करने और शोषण पर अंकुश लगाने के लिए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना है।

Key Points:-

(i) भारत में इस दिन को मनाने के लिए, आंध्र प्रदेश पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किए और महिला एवं बाल सुरक्षा शाखा के अंतर्गत एक पीड़ित सहायता इकाई की स्थापना की। बिहार में, पुलिस ने 31 जुलाई से 14 अगस्त तक 'ऑपरेशन नया सवेरा' नामक दो-सप्ताह का अभियान शुरू किया, जिसके तहत जनवरी 2025 तक 600 से ज़्यादा नाबालिगों को बचाया गया और 144 तस्करो को गिरफ्तार किया गया। कई क्षेत्रों में मानव श्रृंखलाएँ, कार्यशालाएँ और बचाव अभियान आयोजित किए गए।

(ii) गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने रेलवे स्टेशनों के पास मानव श्रृंखला जैसी सार्वजनिक रैलियाँ बनाई और झारखंड में हाँकी प्रशिक्षण जैसे खेल-आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रम

शुरू किए ताकि कमज़ोर किशोरियों को जीवन कौशल विकसित करने और तस्करी के खिलाफ़ मज़बूती हासिल करने में मदद मिल सके। सामुदायिक नेताओं और पीड़ितों ने ज़मीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया।

(iii) ब्लू हार्ट अभियान और वैश्विक आयोजन पीड़ितों का समर्थन करने और बदलाव की वकालत करने के तरीके प्रदान करते हैं। हितधारकों को स्वयं को शिक्षित करने, संदिग्ध तस्करी की सूचना देने, पीड़ितों के आश्रयों का समर्थन करने और कड़े कानूनी उपायों के लिए पैरवी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस संदेश को व्यापक बनाने के लिए #EndHumanTrafficking, #WorldDayAgainstTrafficking, और #SupportSurvivors जैसे हैशटैग का प्रचार करते हैं।

2. भारत में फ्रेंडशिप डे 2025 रविवार, 3 अगस्त को मनाया जाएगा।



भारत में, फ्रेंडशिप डे 2025 रविवार, 3 अगस्त को मनाया जाएगा, जो अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है—यह परंपरा हर साल जारी रहती है। हालाँकि यह अनौपचारिक है, लेकिन इस दिन का भावनात्मक महत्व है, जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के लोग उपहारों, संदेशों और अच्छे समय के साथ दोस्ती का जश्न मनाते हैं।

● मैत्री दिवस की अवधारणा सबसे पहले 1930 में हॉलमार्क कार्ड्स के संस्थापक जॉयस हॉल द्वारा प्रस्तावित की गई थी। बाद में विश्व मैत्री धर्मयुद्ध ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में अपनी 65वीं आम सभा के दौरान 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में नामित किया। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसे 30 जुलाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, भारत जैसे कई देश इसे अगस्त के पहले रविवार को मनाते हैं।

● संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त तिथि के विपरीत, भारत अगस्त के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाने की घरेलू परंपरा का पालन करता है। 2025 में, यह 3 अगस्त को पड़ेगा, जो पिछले वर्षों में स्थापित रीति-रिवाजों के अनुरूप है और स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जाता है। हालांकि यह सार्वजनिक अवकाश नहीं है, फिर भी यह सामाजिक संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है और व्यापक रूप से मनाया जाता है।

● फ्रेंडशिप डे उन दोस्तों के प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का अवसर है जो चुनौतियों और खुशियों में हमारा साथ देते हैं। यह पारिवारिक बंधनों से परे, प्लेटोनिक रिश्तों, विश्वास, वफादारी और भावनात्मक बंधनों के महत्व को दर्शाता है, जिसे अक्सर भावुक नोटों, सोशल मीडिया पर पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले संदेशों और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मनाया जाता है।

Key Points:-

(i) जश्न मनाने के आम तरीकों में दोस्ती के बैंड, हार्दिक संदेश, ग्रीटिंग कार्ड और छोटे-छोटे उपहारों का आदान-प्रदान शामिल है। स्कूल और कॉलेज परिसरों में अक्सर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और युवा सोशल मीडिया पर शाउट-आउट, दोस्ती-थीम वाली सभाओं और सरप्राइज मीट के ज़रिए जुड़ते हैं। यह परंपरा पुरानी यादों और साझा

सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है।

(ii) भारत में, फ्रेंडशिप डे के आसपास व्यावसायिक गतिविधियाँ दिन से पहले ही चरम पर पहुँच जाती हैं—शॉपिंग मॉल और दुकानों में फ्रेंडशिप बैंड, ग्रीटिंग कार्ड और उपहारों की भरमार हो जाती है। विज्ञापन अभियान और त्योहारी प्रचार उत्सव के माहौल को और मज़बूत करते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दोस्ती का जश्न मनाते हुए भावनाओं, उद्धरणों और तस्वीरों से गुलज़ार रहते हैं। वाणिज्य और भावनाओं का यह मेल सांस्कृतिक बंधन को मज़बूत करता है।

(iii) फ्रेंडशिप डे 2025 लोगों से जुड़ने के कई तरीके सिखाता है: पिकनिक, रोड ट्रिप या मूवी नाइट्स का आयोजन; हाथ से बने DIY कार्ड बनाना; दूर रहने वाले दोस्तों के लिए वर्चुअल हैंगआउट की योजना बनाना; और फोटो मोंटाज या फ्रेंडशिप प्लेलिस्ट जैसी व्यक्तिगत डिजिटल सामग्री साझा करना। ये गतिविधियाँ दिन की भावनात्मक तीव्रता को बढ़ाती हैं और स्थायी यादें बनाती हैं।

DEFENCE

1. भारतीय तटरक्षक बल का छठा स्वदेशी तीव्र गश्ती पोत 'अटल' 29 जुलाई 2025 को गोवा शिपयार्ड में लॉन्च किया गया।



29 जुलाई 2025 को, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने ICGS अटल को नौसेना में शामिल किया, जो गोवा

शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा वास्को-द-गामा, गोवा में निर्मित आठ स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए तीव्र गश्ती पोतों (FPV) की श्रृंखला में छठा पोत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित, अटल भारत की तटीय निगरानी और समुद्री बचाव क्षमताओं को बढ़ाता है।

- GSL द्वारा पूरी तरह से स्वदेश में डिज़ाइन और निर्मित, अदम्य श्रेणी के FPVs (अटल सहित) में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जो भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण विशेषज्ञता को दर्शाता है। ये जहाज अमेरिकी शिपिंग ब्यूरो (ABS) और भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) दोनों के दोहरे-श्रेणी प्रमाणन मॉडल का पालन करते हैं।

- 52 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 320 टन विस्थापन वाला, अटल एक नियंत्रणीय-पिच प्रोपेलर (CPP) प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित है, जो 27 समुद्री मील तक की अधिकतम गति प्रदान करता है। इसके प्रमुख अभियानों में तटीय गश्त, द्वीप सुरक्षा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) निगरानी, और तस्करी-रोधी, समुद्री डकैती-रोधी, तथा खोज-और-बचाव (SAR) अभियान शामिल हैं।

Key Points:-

(i) पोत को गोवा में GSL यार्ड में श्रीमती शिल्पा अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें ICG मुख्यालय में प्रमुख आंतरिक वित्तीय सलाहकार (PIFA) रोजी अग्रवाल, IDAS, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय और GSL नेतृत्व के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ब्रजेश कुमार उपाध्याय भी शामिल थे।

(ii) अटल, भारत की 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ICG की क्षमता को सुदृढ़ करता है। ये पोत राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा, अपतटीय परिसंपत्तियों और द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा, मत्स्य पालन संरक्षण और समुद्री घटनाओं के आपातकालीन प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते

हैं।

(iii) यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है और इसने रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है—विशेषकर आपूर्ति श्रृंखलाओं में FPV उत्पादन से जुड़े MSMEs के बीच। पोत की स्वदेशी सामग्री भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमताओं को रेखांकित करती है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी 'प्रलय' मिसाइल का लगातार सफल उड़ान परीक्षण किया।



रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 28 और 29 जुलाई, 2025 को स्वदेशी 'प्रलय' अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए।

- ये परीक्षण भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ओडिशा तट से दूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के दौरान किए गए थे।

- 'प्रलय' मिसाइल एक कम दूरी की, ठोस प्रणोदक, अर्ध-बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। इसे 350 से 700 किलोग्राम तक के पारंपरिक आयुध ले जाने के लिए डिज़ाइन किया

गया है और यह 500 से 1,000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है।

- मिसाइल को दोहरे लॉन्चर विन्यास से सुसज्जित उच्च-गतिशीलता वाले वाहनों से प्रक्षेपित किया गया, जिससे सक्रिय सीमा क्षेत्रों में इसकी त्वरित तैनाती संभव हुई। सफल परीक्षणों ने विभिन्न मिशन परिदृश्यों में इसकी परिचालन गतिशीलता और सटीकता को प्रमाणित किया है, जिससे भारत की सामरिक प्रहार क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

Key Points:-

(i) 'प्रलय' मिसाइल का विकास DRDO के अंतर्गत अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) द्वारा उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला (ASL) और रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (DMRL) जैसी प्रमुख प्रयोगशालाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और कई MSMEs का समर्थन प्राप्त है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 100% स्वदेशी विकास सुनिश्चित करता है।

(ii) मिसाइल की न्यूनतम और अधिकतम रेंज क्षमताओं का आकलन करने के लिए उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के तहत उड़ान परीक्षण किए गए। दोनों प्रक्षेपणों ने सटीक सटीकता के साथ अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, बंगाल की खाड़ी में लक्ष्यों पर प्रहार किया और सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया।

(iii) तकनीकी सत्यापन में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से उन्नत ट्रैकिंग प्रणालियों और सेंसरों का उपयोग शामिल था, जिनमें जहाज पर लगे सेंसर भी शामिल थे। सभी ऑनबोर्ड उप-प्रणालियों ने त्रुटिरहित प्रदर्शन किया, जिससे वास्तविक परिचालन स्थितियों में पूरी तरह से सिस्टम की तैयारी और मिशन अनुकूलता की पुष्टि हुई।

Static GK

Uttar Pradesh (UP)	मुख्यमंत्री (CM) : योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल : आनंदीबेन पटेल
Food and Agriculture Organisation (FAO)	महानिदेशक (DG) : को डोंग्यु	मुख्यालय : रोम, इटली
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Reliance Industries	अध्यक्ष: मुकेश अंबानी, ज्योति देशपांडे	मुख्यालय: मुंबई
CCI	अध्यक्ष: रवनीत कौर आईएस	मुख्यालय: नई दिल्ली
Indian Coast Guard (ICG)	महानिदेशक: परमेश शिवमणि	मुख्यालय: नई दिल्ली
DRDO	अध्यक्ष: समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली
Procter & Gamble (P&G)	अध्यक्ष: जॉन आर. मोलर	मुख्यालय: सिनसिनाटी, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका